Vedanta Journal Of Multidisciplinary Studies
Volume 01, Issue 01, April 2023 | ISSN No.

स्वास्थ्य प्रबंधन में राज्य सरकार की भूमिका : एक अध्ययन

नीतू शर्मा
सहायक आचार्य
वेदान्ता स्नातकोतर महिला महाविद्यालय,रींगस

प्रस्तावना–

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र एवं समाज की मानवीय सम्पत्ति है। व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र एवं समाज के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। अतः जनहित की दृष्टि से सरकार नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा राज्य होने के साथ अपनी कुछ भौगोलिक पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक विशिष्टता रखता है। राज्य में दो तिहाई भाग रेगिस्तानी तथा एक बडा भाग जनजाति बाहुल्य एवं पहाडी है। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना भी कठिन है।

राज्य में साधनों की अल्पता तथा कठिन वातावरणीय परिस्थितियों के कारण राज्य के नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। जिसको पूर्ण करने हेतु राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कृत संकल्पित है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ध्येय समस्त नागरिकों के लिए 'अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य स्तर' की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजंस्थान, जयपुर राज्य के नागरिकों का समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण कर उन्हें कार्य रूप में परिणित करती है। राज्य के समस्त नागरिकों को अधिकाधिक लाभान्वित करने तथा उत्कृष्ट सेवाओं की उपलब्धता के प्रयोजनार्थ विभाग चिकित्सा सुविधाओं का निरन्तर विस्तार कर रहा है। राज्य में क्षय

रोग, मलेरिया, अन्धता, एड्स आदि रोगों पर नियन्त्रण तथा कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के असाध्य एवं गम्भीर रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु 'मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष' तथा जॉच एवं उपचार की सुविधा हेतु 'चिकित्सा सुविधा कार्ड' नामक योजनाएँ राज्य में लागू है, इनसे लाभान्वित होने वालो की संख्या में प्रतिवर्ष उतरोत्तर प्रगति हो रही है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना–

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना का सुदृढीकरण कर राज्य सरकार द्वारा आमजन के स्वास्थ्य में निरन्तर सुधार की प्रक्रिया जारी है। इस योजना का लाभ राज्य की सम्पूर्ण जनता के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के माध्यम से राज्य के लगभग 17550 चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क दवायें उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य के लिये आवश्यक दवा सूची तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान में निम्न प्रकार की दवायें सर्जिकल एवं सूचर्स शामिल है– दवायें–591, सर्जिकल्स–73, सूचर्स–77 । राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही दवाईयों की सूची प्रदर्शित की गई है। आउटडोर रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र ओ.पी.डी. के समयानुसार तथा इन्डोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिये दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के बजट में बढोत्तरी–

इस योजना को प्रारंभ करने से पूर्व राजस्थान प्रदेश की जनता रूग्ण होने पर धन के अभाव में इलाज के चलते जिन्दगी – मौत से जूझते दम तोड़ देती थी लेकिन इस योजना के बाद हर साल अस्पतालों में निःशुल्क दवा, सर्जिकल उपकरण के उपलब्ध होने से आउटडोर एवं इनडोर में मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जिससे वर्ष 2011 में इस योजना का बजट 190 करोड़ का था जिसे वर्तमान में बढाकर अब 965 करोड़ रूपये तक हो गया है।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा कोरोनाकाल में भी मरीजों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुये कोरोना से ग्रसित मरीजो को मंहगी दवाएँ और जीवनरक्षक इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये। केन्द्र सरकार की ओर से दवा की उपलब्धता, उच्च तकनीक, संख्या जैसे मापदण्डों के आधार पर कोरोना प्रबंधन में राजस्थान प्रदेश का नाम अप्रैल 2019 में देशभर में हुई रैकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

योजना के लाभ–

- ❖ उच्च गुणवत्ता व कम लागत की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक और संवेदनशील प्रयास जिसके अन्तर्गत राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- ❖ आम वर्ग के दवा पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है।
- ❖ धन की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं से वंचित वर्ग के लोगों का ईलाज सम्भव हुआ है।
- ❖ दवाईयॉ व इन्जेक्शन आदि के साथ – साथ सामान्यतया उपयोग में आने वाले सर्जिकल उपकरणों जैसे – नीडल, डिस्पोजेबल सीरिंज, आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट व टांको हेतु सूजर्स आदि भी निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे है।
- ❖ सामान्यतया रोगी को तीन दिन की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। अति आवश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियों में कारण इंगित करते हुये 7 दिन तक की दवा उपलब्ध करवायी जा रही है।

निःशुल्क दवा योजना में सर्वाधिक दवाऍ मुफ्त देने और लगभग 100 प्रकार की मुफ्त जॉचों के लिए राजस्थान ने देशभर में अलग पहचान बनायी हैं। साथ ही राजस्थान निःशुल्क दवा वितरण योजना में सर्वाधिक 712 प्रकार की विभिन्न दवाइयॉ निःशुल्क उपलब्ध करवाकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना–

राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 मई वष 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की थी। पहले इस योजना का दायरा 10 लाख रूपये था जिसे बढाकर वर्तमान में 25 लाख रूपये कर दिया गया है। अब प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान का कोई भी परिवार 25 लाख रूपये तक का ईलाज कैशलेस करा सकेगें। इसके लिए परिवार के मुखिया को इस बीमा योजना में पंजीकरण कराना होगा पंजीकरण शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन बीमा योजना के प्रीमियम की राशि सालाना 850 रूपये बीमित परिवार को जमा करानी होगी। राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 33 लाख परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे है। इस योजना द्वारा प्रदेश के 700 निजी अस्पतालों में ईलाज किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग अनवरत रूप से प्रयासरत है कि प्रत्येक अस्पताल में ई.सी.जी. टेक्निशियन नियुक्त किये जाये एन.एच.एम. में कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के पदों को शीघ्र अतिशीघ्र भरा जायें। वर्तमान बजट में राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की जा चुकी है कि इस बीमा योजना में लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की प्रीमियम राशि भी राज्य सरकार स्वंय वहन करेगी।

राज्य सरकार के अनुपम प्रयास से अब आम जनता के मन में स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक जागरूकता भी उत्पन्न हो गई है जिससे अस्पतालों की ओ.पी.डी. संख्या में इजाफा हुआ है।

इन सभी प्रयासों से ही राजस्थान राज्य अब बीमारू राज्य से बाहर निकलने में सक्षम हो पाया है साथ ही राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन की सराहना स्वंय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जा चुकी है। इन सभी प्रयासों को देश के अन्य राज्यों को भी लागू किया जाना चाहिए जिससे देश के हैल्थ इंफ्रास्ट्राक्चर को मजबूती मिल सके जो कि देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखने में एक महत्तवपूर्ण भूमिका निभा सके।

गुणवत्ता परीक्षण–

दवाओ की गुणवत्ता की जांच ड्रग टेस्टिंग लेबोरैट्रीज द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। आरएमएससी द्वारा दवा प्राप्त करने के पश्चात् उसे निषेध क्षेत्र में रखा जाता है एवं पुनः इन दवाईयों की प्रयोगशाला जांच आरएमएससी द्वारा सूचीबद्ध प्रयोगशाला में की जाती है तथा दवाईयों के जांच में खरा उतरने के पश्चात् आम जनता को वितरण के लिये अस्पतालों को जारी की जाती है।

कम्प्यूटराइजेशन–

दवाओं के स्टॉक के प्रबन्धन हेतु जिला औषधि भण्डार को कम्प्यूटराइजेशन कर विशेष ऑनलाइन मानिटरिंग प्रणाली स्थापित की गई है। जिसमें सभी चिकित्सा संस्थानों की सूची के साथ–साथ दी जाने वाली दवाईयों की सूची भी उपलब्ध है।

शोध का उद्देश्य–

प्रस्तुत शोध विषय ' स्वास्थ्य प्रबंधन में राज्य सरकार की भूमिकाः एक अध्ययन' का मुख्य उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की क्षमता बढाने एवं अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में ' मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' चरणबद्ध तरीके से लागू की है। शोध का उद्देश्य वर्तमान में आ रहे सकारात्मक बदलावों एवं प्रवृतियों का अध्ययन

करना है, जिससे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी, और लक्ष्योन्मुख बनाया जा सके।

सन्दर्भ सूची–

1. स्वास्थ्य सेवायें, प्रभात खबर समाचार पत्र, 11 मई 2022
2. आजादी के 70 दशक बाद भी क्यों स्वास्थ्य आज भी नही है। मौलिक अधिकार एनडीटीवी, 21 अक्टूबर 2021
3. केन्द्रिय बजट 2021–22 स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
4. स्वास्थ्य सूचकांक 2017–18 चिन्ताजनक ह ैजन स्वास्थ्य प्रभात खबर 30 जनवरी 2019
5- www.rajswasthya.nic.in
6. चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग प्रगति प्रतिवेदन 2018–19 स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर पृ 59
7. आर्थिक समीक्षा केन्द्रिय वित मंत्रालय, 4 जुलाई, 2019
8. जन स्वास्थ्य अभियान के विश्लेषण पर आधारित सबरंग की रिपोर्ट, जुलाई 17,2019
9. निःशुल्क दवा योजना में सर्वाधिक दवाई मुफत देने ओर करीब 100 प्रकार की थ्तमम जांचों के लिए राजस्थान की देश में धाक है। दैनिक भाष्कर 25 अगस्त 2019
10. चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग प्रगति प्रतिवेदन 2018–19 स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।